दिल्ली-भोपाल-रायपुर सैक्टर पर प्रचालन कर रहा हैं। अभी तक किसी अन्य प्रचालक ने अन्य स्टेशनों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की पेशकश नहीं की हैं।

(ग) जी, हां।

UNDP Report about Human Development Front

1467. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will
the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Human Development Report 1995 of UNDP reveals that Pakistan has done better than India on the human development front;

(b) what are the main constraints for India to lag behind in this regard; and

(c) the steps being taken to improve the performance on the human development front?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (c) According to the Human Development Index (HDI) devised in the UN Human Development Report, 1995 India ranks 134 as against Pakistan ranking 128. This Index has three components life expectancy at birth; educational attainment, comprising adult literacy with 2/3rd weight, and a combined primary; secondary and tertiary enrolment ratio, with l/3rds weight, and income. Government of India is making all out efforts to improve the standard of living of the people through various programmes and attach highest priority to the areas which have formed the basis of calculating HDI in Human Development Report, 1995.

Non-allotment of quarters of Air India Housing Colony

1468. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) how many quarters of Air India Housing
Colony Vasant Vihar, New Delhi are lying vacant and for how long;

(b) whether it is a fact that applications invited from the employees during the month of September, 1993 are pending till date; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) 4 quarters of type "A" and 1 of the "A-l" are vacant at present. Of this, one quarter of "A" type is vacant since September, 1995 and the remaining since November, 1995.

(b) No application received in response to the circular of September, 1993 is pending.

(c) Does not arise.

निजी कम्पनियो के लिए विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

1469. **श्री पशुमपोन त. किरूट्टिनन्** :

श्री भुवनेश्वर कालिता :

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति के अधीन निजी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र को भी खोलने की नीतिगत निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी कंपनियों के लिए कोई विनियामक प्राधिकरण बनाने का फैसला किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तत्थात्मक ब्यौरा क्या हैं और उक्त विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवीप्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बीमा कारोबार को अच्छी तरह से चलाने के लिए और बीमित लोगों के साथ-साथ बीमाकर्ताओं के वैध हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बीमा क्षेत्र के वर्तमान ढांचे में भी विनियागक प्राधिकरण की आवश्यकता हैं। इसलिए सरकार ने वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत अंतरिम बीमा विनियामक प्राधकिरण की स्थापना करने का निर्णय लिया हैं जिसका पदेन अध्यक्ष भारत सरकार के अपर सचिव को स्तर से कम स्तर का नहीं होगा और जिसके 7 सदस्य होंगे जिनमें से 3 से अधिक पूर्णकालिक नहीं होंगे। अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण वैचारिक रूप से "सेबी" के समान एक स्वायत्त बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए विस्तृत विधान